



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ ज्येष्ठ 11, 1940

No. 374]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/ JYAISTHA 11, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

संख्या 32/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 522(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 'डिजिटल आफ़सेट प्रिंटिंग प्लेट्स' (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात पर भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 के तहत लगाये गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 15/24/2016-डीजीएडी, दिनांक 25 अप्रैल 2017, जिसे दिनांक 25 अप्रैल 2017 को भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग I खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमाशुल्क टैरीफ़ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ़ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप-दारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरीफ़ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में सनसेट रिव्यू का काम शुरू किया है;

और जहां कि केंद्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की आवधि को भारत सरकार वित्त-मंत्रालय (राजस्व-विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 2 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 549(अ), दिनांक 25 अप्रैल 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 3 जून 2018, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाये गये वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष, जिसे अधिसूचना संख्या

फा. सं. 15/24/2016/डीजीएडी, दिनांक 23 अप्रैल 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड 1 में दिनांक 23 अप्रैल 2018 को प्रकाशित, में प्रकाशित किया गया है, में इस निर्णय पर पाहुचते हैं कि:

- (i) घरेलू उद्योग (परिमाण और मूल्य दोनों ही दृष्टि से) वित्तीय और आर्थिक दोनों ही प्रतिमानों से स्थिर रहा है, और ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आई है जिसके लिए प्रतिपादन शुल्क को जारी रखने की जरूरत हो;
- (ii) उपयोग करता संघ/ उपयोग कर्ता उद्योग के साथ घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन से उस नुकसान की भरपाई हुई है जिसके अनुचित व्यापार के कारण होने की संभावना रहती है;
- (iii) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिन कीमतों पर सहमति हुई है और घरेलू उद्योग को चोट की अवधि के दौरान और चोट की अवधि के बाद घरेलू उद्योग को जो कीमतें वास्तव में मिली हैं, उससे कीमतें विक्रय मूल्य से नीचे नहीं आयी हैं;
- (iv) निर्यातकों के लिये सहायक कीमतों का रख और आयात के रख से ऐसा नहीं लगता है कि यदि प्रतिपादन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को कोई नुकसान होगा;
- (v) समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार याचिका कर्ता को पूरी कीमत का न मिल पाना ही उस क्षति को पूरा न होने का मुख्य कारण है जो कि कस्टम्स क्लियरेंस के दौरान उत्पाद का गलत विवरण देने के कारण होने वाले 'लीकेज' के कारण 'यूवी-सीटीपी' प्लेट्स के लिये उत्पादों की विक्री कम होने के कारण देखने में आई थी;

और यह सिफारिश की है कि इन तीनों में से किसी भी श्रेणी के उत्पाद प्रतिपादन शुल्क को जारी रखने की जरूरत नहीं है और यह भी सिफारिश कि है कि चीन जन वादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 'डिजिटल आफ़सेट प्रिंटिंग प्लेट्स' के आयात पर लगे वर्तमान प्रतिपादन शुल्क को सीमाशुल्क टेरिफ़ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के धारा(ख) नियम 14 के अनुसार वापस ले लिया जाय।

अतः अब सीमाशुल्क टेरिफ़ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उनपर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20, और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टेरिफ़ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय (राजस्व विभाग) कि अधिसूचन संख्या 51/2012 –सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 3 दिसंबर 2012, जिसे सा. का. नि. 874 (अ), दिनांक 3 दिसंबर 2012 को भारत के राज-पत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व कि गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुये, करती है।

[फा. सं. 354/45/2012–टी आर यू(पार्ट. III)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2018

No. 32/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 522(E).— Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/24/2016 DGAD , dated the 25th April, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 25th April, 2017, had initiated the sunset review in term of sub-section (5) of section 9 A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in

the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Digital Offset Printing Plates' (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2012- Customs (ADD), dated the 3rd December, 2012;

And whereas, the Central Government had extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries up to and inclusive of the 3rd June, 2018 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24/2017-Customs (ADD), dated the 2nd June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 549(E), dated the 25th April, 2017;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification No. F. No. 15/24/2016/DGAD, dated the 23rd April, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd April, 2018, has come to the conclusion that:

- (i) The financial and economic parameters of Domestic Industry (both volume and price) are stable and not evidencing deterioration requiring continuous of Anti-Dumping Duty.
- (ii) The 'MOU' signed by the Domestic Industry with the user association/user industry have led to mitigation of likely injury due to unfair trade.
- (iii) The prices agreed under MOU and actually realized by Domestic Industry during Period of Injury and post Period of Injury do not establish price underselling.
- (iv) The price trends of cooperating exporters and the import trend do not indicate a likelihood of recurrence of injury to Domestic Industry if Anti-Dumping Duty is withdrawn.
- (v) Non realization of full prices in accordance with the provisions of the MoU by the petitioner is the primary reason for non-mitigation of injury that has been noted on account of product underselling for UV-CTP plates due to leakages emanating from mis-declaration of product description during custom clearance;

and has concluded that continuance of Anti-Dumping duty is not warranted on any of the three categories of product and has recommended discontinuance of existing Anti-Dumping Duty on imports of the 'Digital Offset Printing Plates' originating in or exported from China PR in accordance with clause (b) of Rule 14 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 51/2012- Customs (ADD), dated the 3rd December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 874 (E), dated the 3rd December, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/45/2012 –TRU (Pt. III)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.